निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिये विभागों की पहचान

229. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा ऐसे विभागों की पहचान की गई है जिनमें वह निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने का इरादा रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या है ;

(ग) इन विभागों की पहचान करने के लिये सरकार ने क्या मापदण्ड निश्चित किया है ;

(घ) क्या इन विभागो को निजी क्षेत्र को सौप देने के पश्चात् इनमें कार्यरत कर्मचारियों की नौकरियो की सुरक्षा के संबंध में विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए ऐसे किसी विभाग की पहचान नहीं की गई है। केवल विशिष्ट गतिविधियों की पहचान की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Plan to reduce Railway derailments

230. SHRI YERRA NARAYASWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any plan under Government's consideration to drastically reduce railway derailments;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when this plan would be implemented?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF) (a) to (c) Railways constantly endeavour to eliminate all types of train accidents, including derailments. This has yielded results and the numbeer of derailments have been constantly coming down since 1984-85. During 1993.94, derailments came down to 401, an all time low figure which stood at 678 in 1984-85, thus, reflecting an improvement of nearly 41 percent in the decade. However, attention is continuously paid to the following areas:—

(i) Planned renewal and rehabilitation of overaged assets like track, rolling stock and bridges.

(ii) Thorough periodical examination of coaches, wagnos and locomotives in sheds and shops to keep them in good fettle.

(iii) Ultrasonic testing of rails and axles to identify fractures

(iv) Design improvement of certain type of rolling stock.

(v) Upgradation of maintenance skill of staff to suit advanced technologies.

(vi) Identification of vulnerable and derailment-prone secions and induction of necessary inputs therein.

(vii) Training, counselling and monitoring of running staff.

(viii) Constitution of High-level safety teams to conduct intensive inspections of field installations and operating practices to enhance safety consciousness at the grass-root level.

East-Coast Highway Project

231. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state: the present position regarding the implementation of the East-Coast Higway Project in Tamilnadu?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): The East Coast Road in question is a State Highway. Its construction/development, therefore, rests with the State Government of Tamil Nadu as the Central Government is primarily concerned with the roads declared as National Highways only. However, improvement of Madras-Cuddalore section of East Coast Road (167 km) has been taken up by the State Government under Asian Development Bank loan assistance. The estimated cost of the work is Rs. 63 crore and present overall progress is 40 per cent.

इलाहाबाद में यमुना नदी पर पुल का निर्माण

232. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में यमुना नदी पर सड़क पुल के निर्माण-काय को शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ख) निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा है ?

जल-भतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इलाहाबाद जिले में यमुना नदी पर एक नए सड़क-पुल के निर्माण को अनुमोदन दे दिया गया है और ऋण सहायता के बारे में ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फंड (जापान) के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ऋण की अपेक्षाओं के अनुसार, परियोजना का पूरक व्यावहार्यता अध्ययन और ब्यौरेवार इंजीनियरी अपेक्षित होती है, जिसके लिए कार्रवाई की जा चुकी है। ऋण को कार्यान्वयन अनुसूची के अनुरूप परियोजना का निर्माण कार्य अक्तूबर, 1996 से शुरू करने और मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

नई सड़क-नीति का कार्यान्वयन

233. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में सड़क मार्गों के सुधार और विस्तार हेतु निजी क्षेत्र की भागीदार बनाने के लिए नई सड़क-नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रारूप की रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नई सड़क-नीति के कार्यान्वयन की घोषणा कब तक करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क आधारित सुविधाओं को बी०ओ०टी० (निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण) के आधार पर निर्माण, रख-रखाव और प्रचालित करने में निजी क्षेत्र को सहभागी बनाने पर विचार कर रही है। तथापि, इस संबंध में नीति एवं दिशा-निर्देशों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए इस स्तर पर वह स्थिति विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

Illegal activities of the Truckers' Union

234. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be peased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item pubished in the "Hindustan Times" of 6th November, 1994 captioned "Truckers" unions